to the country, convey to all organs of the society and convey to all the organs of the Constitution that the public is supreme, and we will have to follow them, and we will have to change the rules, regulations and the law, if necessary, and if any one of them attacks each other, they have to be protected, but not by giving any special privilege to any section of these three wings. Thank you very much, Sir, for the opportunity which you have given to me.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, do you want to say something?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for providing wide opportunity to me and all the hon. Members to reflect on an important issue like this. I think, in a situation like what we have discussed, ultimately, the sovereign will of the people will prevail.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. Just a minute please.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: You wanted me to say that. So, all three wings will have to reflect that.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, there is one problem. He is a mover of the Resolution and he also has a right to reply. So, you only request for withdrawal.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I request the hon. Member to withdraw this Resolution as my reply has already reflected the full body of the Resolution which was presented before the hon. House. In view of all that, I make an appeal to the hon. Member to withdraw his Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): So, Mr. Ramdas Agarwal, are you withdrqwing the Resolution?

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि कानून बनाने की उनकी इच्छा है... He wants that the law should be made. But, Sir, in our country, in our administration, in our States, कोई भी गवर्नमेंट होगी, कानून बनाने में इतना समय, इतनी देरी होती है कि उसकी सारी भावना और उसकी सारी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि भावना और आवश्यकता समाप्त न हो, उससे पहले आप कोई अच्छा कानून बनाकर के इस देश के अंदर कोई अच्छी व्यवस्था लाने का प्रयास करें। अगर आपका यह एश्युरेंस है तो मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri O.T. Lepcha to move a Resolution regarding the development of the State of Sikkim.

Need to prepare an Action Plan for all-round development of Sikkim

SHRI O.T. LEPCHA (Sikkim): Sir, I move the following Resolution:

"Having regard to the fact that —

(i) Sikkim was merged to the Union of India out of emotions in the year 1975;

(ii) the Hindi speaking people of the State are proud to be Indian;

(iii) Sikkim is the land locked State with no air and rail link to the State;

(iv) the State shares its international borders with Nepal, Bhutan and China;

(v) Sikkim is popularly called "mini Switzerland" of India with abundance of natural and scenic beauty including Mt. Kanchenjunga at its peak;

(vi) even after 35 years of its merger, there is not much development in the State;

(vii) there is no representation of the people of Sikkim in high Constitutional posts and other higher authorities;

(viii) only life line of the State *i.e.*, the National Highway No 31-A remains disturbed throughout the year; and

(ix) there is resentment in the peace loving people of Sikkim in view of its neglect, this House, therefore, in order to bring the people of Sikkim in the mainstream of the Country, urges upon the Government—

(a) to prepare an action plan for an all round development of the State of Sikkim;

(b) to connect the State with air and rail link at the earliest;

(c) to improve the road infrastructure in the State by acceding to the proposal received from the State Government;

(d) to consider appointment of the people of Sikkim to the Constitutional posts and in other higher authorities;

(e) to develop Sikkim as an international tourist destination in view of its vast potential; and

(f) to preserve the natural reserves of the State."

Sir, I am thankful to the Vice-Chairman that I have been given the opportunity to move the Resolution in this House. I represent the State of Sikkim in the House and I am the sole representative of the State. In view of the lack of development in the otherwise a potentially strong State of Sikkim, I have to move a Resolution specifically pertaining to the State. Sikkim merged with the Union of India in 1975. The people of Sikkim are peace-loving and proud to be Indian. However, even after 35 years, not much progress has been made in the State. There is no person representing the State of Sikkim at the highest constitutional post and other highest place. It is a landlocked State and connectivity to the State is one of the major problems at present.

उपसभाध्यक्ष महोदय, 35 साल बीत जाने के बाद सिक्किम राज्य के बारे में कुछ बातें इस सदन में रखने का जो अवसर मिला है, यह एक गर्व और फख्र की बात है। सर, 1975 में एक रिफ्रेंडम – जनमत से हम लोग इस देश के साथ इम्मोशनल इंटीग्रेट हुआ है। आज 35 साल बीत जाने के बाद सिक्किम के लोगों को भी यह महसूस हो रहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से जो हक और अधिकार एक राज्य को मिलना चाहिए और देना चाहिए, यह सही में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। सिक्किम कैसा स्टेट है, अपने देश का सिक्किम कैसे बन सकता है, यह एक सपना सिक्किम के लोगों का है, सिक्किम

की सरकार का है, सिक्किम के मुख्य मंत्री का है। इसलिए यह बात आज मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। सिक्किम देश का सबसे छोटा प्रदेश है, यहां शांति है, जो आप लोगों को मालूम है। सिक्किम का टोटल एरिया 96 स्क्वायर किलोमीटर है। वहां की जनसंख्या पांच लाख चालिस हजार है और पौपुलेशन डेंसिटी 76 पर्सन्स पर-स्क्वायर किलोमीटर है। वहां का पर-केपिटा इन्कम 39 हजार 632 है और लिट्रेसी रेट 82 परसेंट है। वहां की ऑफिसियल लैंग्वेज हिन्दी, अंग्रेजी और नेपाली है। ऐसा एक छोटा-सा प्रदेश जो तीन अंतर्राष्ट्रीय, थ्री इंटरनेशनल बार्डर्स के साथ जुड़ा हुआ है, एक साइड में चीन है, एक साइड में भूटान है और एक साइड में नेपाल है। आपको पता है कि बहुत सेंसेटिव होने के बावजूद वहां पर आज तक शांति है, अच्छा है। सिक्कम के लोग देश के लिए अनपैड सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन आज 35 साल बीत जाने के बाद में ऐसा एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, जिसकी जीवन रेखा 31 नेशनल हाईवे के अलावा कुछ नहीं है। सर, 35 साल बीत जाने के बाद में भी एक राज्य को देश के हवाई अड्डे से न जोड़ना, एयरपोर्ट से नहीं जोड़ना, एयर लिंक से नहीं जोड़ना और उसका अल्टरनेटिव विकल्प नेशनल हाईवे नहीं होना, यह बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। आज सिक्किम के लोग गर्व करते हैं, फख्र करते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन हैं और सारे लोग वहां पर हिन्दी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, वहां ज्यादा शांति होने के कारण से हो, या किस कारण से हो, मैं यह तो कह नहीं सकता हूं कि सिक्किम की अनदेखी हुई है, यह बता नहीं सकता हूं, फिर भी, कभी-कभी हम लोगों को महसूस होता है कि एक स्टेट को जो केन्द्र सरकार की ओर से मिलना था, जो हक, अधिकार और मदद मिलनी चाहिए थी, वह आज तक नहीं मिला है। इसीलिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक बैकवर्ड स्टेट जो लैंड लॉक्ड है, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हैं ? केन्द्र सरकार की ओर से उस राज्य के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? मैं अपनी स्टेट के पोटेंशियल के बारे में यहां जानकारी देना चाहता हूं और उस पोटेंशियल से पता चलता है कि सिक्किम देश के लिए कितना महत्वपूर्ण राज्य है और कैसे अपने देश में यह राज्य स्विटजरलैंड की तरह से बन सकता है। हिल स्टेट के कारण वहां टोटल 28 माउंटेन हैं और वहां लेक्स एंड वैट लैंड 227 हैं और हॉट स्प्रिंग 21 हैं। इसी तरह से मेमल्स की 150 वैराइटीज़ हैं, बड्र्स 552 हैं, बटरफ्लाई की 690 एंड फिश की 48 वैराइटीज़ हैं । फलावरिंग प्लांट्स 4500 हैं और Rhododendron जो दूसरा दुनिया में इतना नहीं है, Rhododendron जिसको ग्रास भी बोलते हैं, इसकी 36 वैरायटीज़ सिक्किम में हैं। इससे बड़ी चीज़ है, सर, यह orchid की वैरायटी है, यह वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट orchid वैरायटी है; इसकी 515 वैरायटीज़ सिक्किम में मिलती हैं। इसके अलावा सिक्किम में टोटल 82.32 परसेंट फॉरेस्ट कवर स्टेट है। इतना ही नहीं, हाईडल पावर में टोटल 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन वहां होता है। सर, वहां पर सबसे बड़ी चीज़ माउंट कंचनजंगा, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, जिसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक रोज सिक्किम में कम से कम 50-60 हजार की संख्या में आते हैं।

सर, ये सब चीजें हमारे देश के अपने ही एक राज्य के अंदर हैं। इस राज्य को डेवलेप करने के लिए, इसको सुचारू रूप से एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म, पर्यटन स्थल बनाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से बहुत सारी मदद की जरूरत है। इन में से कुछ चीजें जो होनी थीं, वे आज तक भी नहीं हुई हैं। मैं आज इस सदन में बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 35 साल बीत जाने के बाद भी सिक्किम से आज तक केन्द्र में एक भी कांस्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई रिप्रजेंटेटिव नहीं है। आप मंत्री की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज तक किसी कमीशन का कोई मैम्बर भी सिक्किम से नहीं बनाया गया है। जब इलैक्शन होता है और केन्द्र में सरकार का गठन होता है, सिक्किम की ही एक ऐसी पार्टी है, जो पार्टी सरकार में आती है, उसको अन-कंडिशनल समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। हम लोगों की कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हम लोग देश के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। यहां से जितने भी सिक्किम कैडर के IAS, IFS और IPS आफिसर लोग यहां के लोगों की मदद करने के लिए, सिक्किम डेवलेपमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार से माननीय मंत्री लोग तथा बड़े लोग यह रेकमेंड कर देते हैं कि इन लोगों को वापस बुलाया जाए। 60 परसेंट IAS आफिसर, IPS आफिसर और IFS आफिसर सब दिल्ली में हैं। इस तरह से ये 60 परसेंट लोग दिल्ली में रहते हैं और जो बाकी 40 परसेंट लोग हैं, वे सिक्किम में रह रहे हैं। ऐसी हालत सिक्किम की है। मैं सिक्किम को लैंड लॉक्ड स्टेट

कह रहा हूं। यह 31 National Highway सिक्किम के लिए एक ही लाइफ लाइन है। जब समर में बारिश होती है, तो लैंड स्लाइडिंग के कारण यह बंद हो जाता है। कभी-कभी गोरखालैंड वाले बंद कर देते हैं, वे पूरा National Highway जाम कर देते हैं। हम लोगों को दिल्ली के सब बड़े लोगों को हाथ जोड़कर कहना पड़ता है कि इस National Highway को खोल दो, क्योंकि बंगाल की अपनी दूसरी बात है। हम इस तरह से कितनी विनती करें? जब बंगाल में गोरखालैंड का एजिटेशन होता है, तो सिक्किम जाम हो जाता है। वहां जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है तथा और न ही कोई साधन है। हमने केन्द्र सरकर से 6 साल पहले एक हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन आज तक वह हेलीकॉप्टर भी हम लोगों को नहीं मिला है। मैं यहां पर किसी माननीय मंत्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि जब National Highway बंद हो जाता है, उस टाइम पर सिक्किम के लोग क्या खाते होंगे, क्या पीते होते होंगे तथा वहां के आफिर्स क्या काम करते होंगे? वे सिक्किम की जनता को कैसे सुविधाएं पहुंचाते होंगे, यह किसी को पता नही है। जो सिक्किम के लोगों की व्यथा है, वेदना है और दर्द है, वह केवल सिक्किम के लोगों को ही पता है। मैं अभी हाउस के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस 31 National Highway की स्थिति ऐसी है कि वहां पर गाड़ी चलाना तो दूर, यदि आप वहां पर घोड़ा भी चलाएंगे, तो वह भी नहीं चलेगा। वहां पर घोड़ा भी गिर जाएगा क्योंकि वहां के रास्ते ही ऐसे हैं। हम लोगों ने इस बारे में काफी लिखकर दिया है कि इस 31 National Highway की मरम्मत की जाए। कल ही लोक सभा में मेरे एक मित्र ने इस 31 National Highway के बारे में प्रश्न पूछा था। मंत्री जी ने यह रेप्लाई दिया कि I have no idea. यह काफी बड़ी बात है कि एक मंत्री जी को 31 National Highway के बारे में मालूम नहीं है। सर, यह 31 National Highway; Sivok से Nathula तक कम से कम चार वर्ष पहले डबल लेन करने के लिए सैंक्शन हुआ था, लेकिन अभी उसका दस किलोमीटर तक का काम भी कम्पलीट नहीं हुआ है। सन् 2006 में Nathula ट्रेड रूट की ओपनिंग हुई थी। उस समय चाइना साइट में कोई रास्ता नहीं था। अब 2006 के बाद उन लोगों ने दो साल के अंदर टू लैंडिंग रूट ऐसा बना दिया है, जो बार्डर से उधर चला गया है। हम लोगों के Highways जैसे थे, वैसे ही हैं। हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताते हैं कि फॉरेस्ट इंवायरन्मेंट से क्लियरेंस नहीं मिली है।

अरे बाबा, यह Forest and environment Department कहां का है? यह फॉरेन कंट्री का है या अपने देश का है? एक विभाग रास्ते सैंक्शन कर रहा है और दूसरे विभाग को मालूम नहीं है उसको कैसे करे, क्या करे। यह सब क्या है? अपने देश में यह सब क्या है? यह भी एक विडंबना की चीज है। क्यों ऐसे ऑब्जेक्शन्स करते हैं? यह नेशनल हाई-वे की बात है, अपने प्राइवेट रोड की बात नहीं है। सर, यह बात नेशनल हाई-वे 31 के बारे में है। दूसरी एक सिम्पल चीज है, लेकिन हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कराना चाहता हूं कि सिलिगुड़ी के सामने सेवोक टू सिलिगुड़ी के बीच में जस्ट हाफ किलोमीटर के अंदर आर्मी के लोगों ने पूरा बैरीकेड लगाया है। कैंटीन जाने के लिए एक बैरीकेड लगाया है, मेजर के दफ्तर में जाने के लिए बैरीकेड लगाया है, एक बैरीकेड मैस में जाने के लिए भी लगाया है। हर किलोमीटर में दस बैरीकेड लगाए हैं। सिक्किम की जितनी भी गाड़ियां वहां जाती हैं, उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हम लोगों को वहां खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि आर्मी ने वहां पर ऐसा बैरीकेड लगाया है। इन्होंने नेशनल हाई-वे 31 को भी ऐसा कर दिया है। यह कहां तक न्याय की बात है? यह रिकॉर्ड करने की बात है। माननीय मंत्री जी ने इसे रिकॉर्ड किया है, यह बहुत अच्छा विषय है। वहां के नेशनल हाई-वे की इस तरह की स्थिति है। अभी आप रैलिंग की बात तो छोड़ ही दीजिए...(**व्यवधान**)... डिफेंस मिनिस्टर हाउस में नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर आप यह सब नोट करें तो ये इम्पोर्टेन्ट चीजें हैं। अगर यह ऐक्शन में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह

से यह सिक्किम स्टेट की दुखभरी कहानी ही नहीं है, यह यथार्थ है। केंद्र सरकार इसके ऊपर निगरानी रखेगी, ऐसा मैं सोचता हूं। उससे बड़ी चीज है कि इतना सब होते हुए भी हम लोगों पर बहुत सारा प्रेशर है। इधर से माओइस्ट, उधर से माओइस्ट, उधर से उल्फा पता नहीं क्या-क्या है। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सिक्किम को अभी तक अक्षुण्ण रखा है, टच नहीं होने दिया है। यह देश के लिए सबसे बड़ी चीज है। मेरे चीफ मिनिस्टर कहा करते हैं कि हम लोग सिक्किम की जनता हैं। मैं एक नौकर हूं। सारी सिक्किम की जनता एक अनपेड सोल्जर है। हम लोग बिना पैसे लिए देश की सुरक्षा का काम करते हैं। मेरे मुख्य मंत्री ऐसा कहते हैं, यह बात सही है। यह आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। सिक्किम की डेवलपमेंट जिस तरह से होनी चाहिए, यह अभी एक ग्रोइंग स्टेट है, हम लोग अपने स्टेट का रेवेन्यू इकट्ठा करके फंड बना कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी केंद्र सरकार की ओर से जो फंड हम लोगों को मिलता है, वह फंड एज पर दि पॉप्युलेशन कर देंगे तो क्या होगा? हम लोग 5.40 लाख हैं। यह इतना बड़ा राज्य है, इसमें क्या करेंगे। एज पर पॉल्युलेशन कितना मिलता है? ये सब चीजें हैं। हम लोग स्पेशल कैटेगिरी में हैं। स्पेशल प्रोविजन 371 (f) के अंतर्गत हम लोगों को रखा गया है। वहां के लिए संविधान में ऐसा प्रावधान है, लेकिन कभी-कभी हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये लोग संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। यह क्या है, पता नहीं है। प्रोविजन तो है, लेकिन एक बकरी के लिए ऐसा खोर बना दिया है कि तुम इधर बैठो। वहां घास भी नहीं है, पानी भी नहीं है। वह बकरी कितने दिन जिंदा रहेगी? एक प्रोविजन देकर रखा है। कुछ नहीं है। इस तरह से आज सिक्किम की जनता की एक दुर्दशा है। मैं केंद्र सरकार से request करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि सिक्किम में बहुत सारा पोटेंशियल है। वह पोटेंशियल स्विटजरलैण्ड में नहीं है। बृज भूषण तिवारी जी और मैं स्विटजरलैण्ड विजिट करके आए हैं। हम लोगों ने स्विटजरलैण्ड को नजदीक से देखा है। जितना पोटेंशियल अपने राज्य सिक्किम में है, उतना पोटेंशियल उस देश में नहीं है। हम लोग स्विटजरलैण्ड से भी बेहतर अपने देश में एक मिनी स्विटजरलैण्ड तैयार कर सकते हैं।

यह अपने देश के लिए है, यह सिक्किम की जनता के लिए नहीं है या किसी और दूसरी प्रांत, दूसरी स्टेट के लिए नहीं है। यह देश के लिए एक फख्र की बात होगी, गर्व की बात होगी। वहाँ पर हम लोग एक world class tourist destination तैयार कर सकते हैं, ताकि संसार के लोग विश्व के 3rd highest peak माउंट कंचनजंगा को देखने के लिए और हिन्दुस्तान की सबसे सीधी-सादी जनता, जो एक disciplined soldier है, उन्हें देखने के लिए सारे देश के लोग वहाँ आएंगे। इससे देश की तरक्की होगी, नाम होगा। इसलिए हम लोगों की जो कमी या कमजोरी है, उसे ध्यान में रखते हुए एक पूरे एक्शन प्लान की तरह नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में अगर केन्द्र सरकार सिक्किम को आगे बढ़ाने की योजना तैयार करे, तो शायद सिक्किम के लोगों के साथ न्यायपूर्वक काम होगा। मैं इसीलिए यह resolution लाया हूँ, ताकि सिक्किम को सचमुच हिन्दुस्तान की एक पहचान मिले और सिक्किम की जनता को अपना हक और अधिकार मिले। Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Lepcha. Shri Silvius Condpan.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI R.P.N. SINGH): Sir, can I just intervene to respond to hon. Members reference to the position of Highways in the State of Sikkim?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It can be done at the time of the reply.

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I support the Resolution moved by my hon. colleague, Shri O. T Lepcha. The hon. Member has very clearly and elaborately put before the House the different areas in which Sikkim and its people have been suffering. There is no point in disagreeing with the grievances that the hon. Member has highlighted before the House.

Sir, Sikkim may be a small State but, at the same time, from the national security and also from the internal security point of view, Sikkim is very important. Sikkim needs all kinds of attention from the Central Government, and much more than what has been given so far. This is not a fact that ever since Sikkim was merged with India in 1975, nothing has been done. That is not true. Much has been done but, yes, much more has to be done for the people of Sikkim and for the development of Sikkim State. From my experience in Parliament, I can say that I have come across a good many legislations, a good many Acts for the welfare and benefits of the people of Sikkim; all those had been brought forward and passed at the initiative of the Central Government. The Central Government recently passed an Act giving a Central university to the people of Sikkim. That shows how much is the Central Government interested in giving higher educational facilities to the people of Sikkim.

Now, the one of the major points that my learned friend has highlighted is Sikkim's connectivity with the rest of the country by road and by air. Of course, there is some difficulty for the Government so far as the topographical situation of Sikkim is concerned. Similar is the case of Arunachal Pradesh. The topographical disadvantages are there in the construction of roads, in the construction of air strips and so on but there is also as much necessity of connectivity for the country as a whole as for the people of Sikkim.

The other side is also very important. But the difficulty for the Government is to pursue the schemes of development, so far as the questions of giving them better roads, more roads and more air connectivity are concerned. Yet, it is not a fact that the Government does not want to give. But, at the same time, the Government has to think and find out ways and means to give them air linkage, to give them rail linkage and to improve the road system for the people of Sikkim. He has mentioned, in his speech, that whenever there is agitation, followed by bandh, in the neighbouring State of West Bengal, Sikkim is the State which is the worst sufferer, and till the grievances in the neighbouring State are resolved, the people of Sikkim, without any reason, will continue to suffer from road blockade and from other transportation point of view. He has already mentioned that there has been a long cry that, at least, instead of air link, there should be helicopter linkage with the State, but that has also not materialised. I think, for a small State like Sikkim, on medical ground, on emergency ground, on border emergency, helicopter communication facility was a must by this time. But, that is yet to come. So, I request the Government to see that air linkage, road linkage and other communication facilities are to be given to the people of Sikkim, the border State. He has already mentioned that Sikkim is

surrounded by three international borders, *i.e.*, Nepal, Bhutan and China. It is a very sensitive area than other bigger States of our country. The bigger States of our country have no such problem in the border areas what Sikkim has. On the other hand, our learned friend has made us to understand that Sikkim is rich in its natural resources, and the Government of India should tap it; should exploit it in the interests of the country and, particularly in the interests of the people of Sikkim.

Now, the Government of India is talking about development of tourism. The potential of tourism is much more available in Sikkim, as has been transpired in the speech of our learned friend, who is the mover of this Resolution. Why should we worry about developing the international tourism? If we develop Sikkim, it will attract the international tourists to Sikkim. The tourists are now limiting up to Darjeeling. They cannot go beyond Darjeeling. If they go up to Sikkim, then Sikkim will earn a lot of foreign exchange for our national exchequer.

Sir, again, I would like to stress on the point that Sikkim immediately requires the steps taken by the Central Government for preserving the natural resources. We have passed the Act for giving rights to forest land. I think, that is also applicable to the State of Sikkim. And, this spoiling the forest resources at the cost of forest rights is not in the interest of Sikkim, which is a small State, which is very much rich, as on today, on natural resources. If it is allowed there, then, that will be spoiled. That will culminate in the destruction of the environment. So, this point has to be taken into consideration. Now, my friend has expressed his concern that even after 35 years of their being part of India, the people of Sikkim did not get any constitutional posts. He has elaborated as to what are those constitutional posts.

It is a very important point. I think, the hon. Ministers, who are taking note of all these points will take a note of this also. I think, getting back the IAS officers, IPS officers and IFS officers on deputation frequently, and leaving the people of Sikkim at the mercy of the State service officers is not going to do justice. That is delinking the people of Sikkim with the rest of the Central administration. That should not be there. It is happening not only in Sikkim, but in the north-eastern States also. It happens to Meghalaya, it happens to Arunachal Pradesh, it happens to Nagaland and Mizoram. They are suffering in that way. So much of deputation to Delhi leaving the State in the hands of the State civil officers. This is a serious point he has raised. This is also applicable for the rest of the north-eastern States and Sikkim is one of the north-eastern States.

I support this Resolution on these contexts. I hope, the Government would give a very, very positive response to what my learned friend has brought out in this forum of Parliament, for the knowledge of the Government to take action on them. With these few words, I support the Resolution. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri S.S. Ahluwalia; I think, he will come. Shri Saman Pathak; he is not here. Shri Brij Bhushan Tiwari now.

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, प्रस्तावक महोदय ने सिक्किम के विकास के सिलसिले में जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और साथ-ही-साथ जो उनकी पीड़ा और उनका रोष है, उसे भी मैं जायज मानता हूँ।

महोदय, यह बात प्रस्तावक महोदय ने भी कही और उसके अनुमोदन में अभी एक वक्ता महोदय ने भी बतायी कि जो सिक्किम प्रदेश है, वह किस प्रकार से सामरिक दृष्टि से और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्किम की जनता बहुत ही शान्तिप्रिय है और उसका दिली लगाव भारत की जनता से है, भारत के लोगों से है। हमारा और उसका सम्बन्ध सांस्कृतिक है और भाषाई भी है, लेकिन जिस तरीके से, उसका विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं हो पाया। यह सही है कि जब से उसका भारत में विलय हुआ, केन्द्र सरकार की तरफ से उसे मदद जरूर मिली, परन्तु उसका जो विकास है, उसकी गति चींटी के समान है। वह एक बहुत महत्वपूर्ण सूबा है, प्रदेश है। जैसा अभी प्रस्तावक महोदय ने स्वयं कहा कि उसकी जो सीमाएँ हैं, वे नेपाल से, चीन से और भूटान से मिलती हैं तथा इससे सटा आंतरिक प्रदेश पश्चिमी बंगाल है।

महोदय, मैं पिछले साल सिक्किम गया था। वहाँ मुझे नाथू ला जाने का भी मौका मिला। NH-31A, जो वहाँ की जीवन-रेखा है, वह सड़क भी हमने देखी। नाथू ला तक जाने के लिए जो सड़क है, उसे तेजी से बनना चाहिए था। वह बहुत खराब स्थिति में है। प्रस्तावक महोदय ने सही कहा कि मोटर कौन कहे, घोड़ा भी उस रास्ते पर नहीं चल सकता है, वह ऐसी खराब स्थिति में है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रदेश हमारी सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण हो और उस प्रदेश की एक मात्र सड़क की ऐसी दुर्दशा हो, तो हम विकास क्या करेंगे? केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुल जाने से ही तो सारा विकास नहीं हो जाता?

जब तक उसके चतुर्मुखी विकास की कोई कल्पना या कल्पनाशीलता हमारे अंदर नहीं है, तब तक हम उस प्रदेश का सही रूप में विकास नहीं कर सकते। यह केवल सिक्किम का ही दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी सीमावर्ती प्रदेश हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की हमारी तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए, वह हम नहीं कर पाते। अभी प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में बताया कि चाहे आई.ए.एस. अधिकारी हों या आई.पी.एस. अधिकारी, जिन अधिकारियों की भी इन प्रदेशों में नियुक्ति होती है, वे वहाँ काम नहीं करना चाहते, वे वहाँ जाना नहीं चाहते। अगर उनका वहाँ ट्रांसफर होता भी है या उनकी वहाँ नियुक्ति होती भी है तो वे जोर-शोर की सिफारिश लगाकर वहाँ से चले आते हैं। अगर हमारे अधिकारी वहाँ नहीं जाएंगे, अगर हमारे लोग वहाँ नहीं जाएंगे और अगर वहाँ के लोगों से हमारा संपर्क नहीं होगा, तो हम कैसे भावानात्मक एकता हासिल कर सकते हैं? हम देश की एकता को कैसे मजबूत कर सकते हैं? यह केवल भाषणों से नहीं होगा। इसलिए हमें दोनों स्तरों पर प्रयास करना होगा। एक तो विकास के स्तर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि अगल-बगल के जो सूबे हैं, जहाँ उपद्रव है, अशांति है, उस उपद्रव और अशांति का कारण क्या है? जहाँ इस प्रकार के सशस्त्र संगठन काम करते हैं, आतंकवादी संगठन काम करते हैं और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनको हम सुहाते नहीं हैं, जो हमारे विकास को देख कर जलन रखते हैं, वह हमारे विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं, वे इन प्रतिकूल परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठा कर हमारे खिलाफ एक अजीब प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा कि हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं, उनको भावना की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और संसाधनों की दृष्टि से कैसे जोड़ा जाए। यह ठीक ही कहा गया कि सिक्किम के लोग शांतिप्रिय हैं। अभी वे उम्मीद लगाये हुए हैं कि केन्द्र की सरकार शायद हमारे साथ न्याय करे, परन्तु अन्य प्रदेशों के लोगों की तरह ही अगर वहाँ के लोगों का धीरज, वहाँ के लोगों की हिम्मत भी टूट जाएगी और वहाँ भी कुछ उपद्रवी तत्व इस प्रकार का वातावरण बना देंगे तो हमारे लिए यह कितनी खतरनाक स्थिति होगी, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य जी ने कहा कि वहाँ भौगोलिक परेशानी है, वहाँ पर ट्रॉपिकल दिक्कत है, परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गयी हो और आप दुनिया का एक बड़ा पावर बनने का ख्वाब देखते हों, वहाँ ऐसी चुनौतियों को ध्यान में रख कर हमारी तैयारी होनी चाहिए। मैंने नाथूला के रास्ते में चीन के इलाके में देखा कि वहाँ किस प्रकार से चौड़ी सड़क बन गयी है और हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण सामरिक सड़क है, वह आज तक पूरी नहीं हो पायी। इसमें कितना साल लग जाएगा? इस प्रकार की हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी तैयारी होनी चाहिए। आखिर कारण क्या है? पैसे की कमी है या इंजीनियर्स की कमी है अथवा उसकी देखभाल करने वालों की कमी है? इसकी मॉनिटरिंग होती है कि नहीं होती है? क्या कारण है कि जिस सड़क को कब का पूरा हो जाना चाहिए था, वह सड़क अब तक पूरी नहीं हो पायी है? इसलिए मेरा यह कहना है कि सिक्किम के विकास को दृष्टि में रख कर हमें काम करना चाहिए।

प्रस्तावक महोदय के साथ मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि स्विट्जरलैंड के मुकाबले सिक्किम में जो प्राकृतिक सम्पदा है या वहाँ टूरिज्म की दृष्टि से विकास की जो संभावना है, वह कई गुना ज्यादा है। वहाँ पर एक "टॉप आफ दि यूरोप" है। "टॉप आफ दि यूरोप" 13 हजार फुट की ऊँचाई पर है। वहाँ लोगों ने सौ साल पहले ट्रेन बना दी। उन्होंने ग्लेशियर्स के अंदर केव्स बनाये। स्विट्जरलैंड के टूरिज्म की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत "टॉप आफ दि यूरोप" है। लोग वहाँ उसी को देखने जाते हैं, शहर को देखने नहीं जाते हैं, शहर तो वे हर जगह देख लेते हैं। वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उससे कई गुना अच्छा हमारे यहाँ है। यहाँ सिक्किम की पहाड़ियाँ हैं, कंचनजंघा की पहाड़ियाँ हैं, हरी-भरी और खूबसूरत और भी ऐसे कई स्पॉट्स हैं, जिनका हम विकास कर सकते हैं।

तो हमें कम से कम ये जो लिंक हैं, ये जो यात्रा के सूत्र हैं, उनके द्वारा सिक्किम को जोड़ने की, जहाज से जोड़ने की, ट्रेन से जोड़ने की, सड़क से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और इससे हमें कितना फायदा होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इससे केवल सिक्किम की जनता का ही फायदा नहीं होगा, सिक्किम की जनता का यह फायदा जरूर होगा कि वहां रोजगार के साधन मिलेंगे, क्योंकि वहां रोजगार का कोई साधन नहीं है। कोई कारखाना वहां लग नहीं सकता, पर्यावरण की दृष्टि से तमाम प्रकार की आपत्तियां होंगी। वहां पर पुरानी जातियों के लोग हैं, पुराने कल्चर हैं – लेप्चा संस्कृति और दूसरे समूह भी हैं, वे केवल खेती करते हैं। खेती भी मुनाफे की नहीं है और विकास का कोई साधन वहां है नहीं, दुकानदारी, व्यापार की भी संभावना नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत कम है। तो जब बाहर के लोगों का वहां पर्यटन होगा, यातायात की सुविधाएं बढ़ेंगी, देश के भी और बाहर के भी, जब दोनों तरह के पर्यटक वहां जाएंगे, तो वहां पर विकास अपने आप होने लगेगा। क्योंकि विकास के बारे में यह बात है कि अगर आप किसी क्षेत्र को सड़क से जोड़ दीजिए, ट्रेन से जोड़ दीजिए, वायु मार्ग से जोड़ दीजिए, इस प्रकार जब लोगों के आने-जाने की सुविधा हो जाएगी तो विकास अपने आप होने लगता है। आज लोगों के पास पैसा भी है और वे जाना भी चाहते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वे नहीं जा पाते, इसलिए अगर हमने ये सुविधाएं प्रदान कर दीं, तो उनसे विकास होगा। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मन की, दिमाग की बनावट है, उस बनावट को बदलना पड़ेगा। केवल राष्ट्रीय एकता की धुन लगाने से राष्ट्रीय एकता कायम नहीं होगी, राष्ट्रीय एकता कायम करने के दो तरीके हैं – समबोध और समलक्ष्य। अगर हम वहां के लोगों की आकांक्षाओं का, वहां के लोगों के दर्द का, वहां के लोगों की उम्मीदों का अहसास नहीं करेंगे और अगर हमारा दर्द उनका दर्द नहीं बनेगा तथा उनका दर्द हमारा दर्द नहीं बनेगा, तो हम कैसे कहेंगे कि वे भारत के नागरिक हैं या हमारा उनका दिली रिश्ता या भावनात्मक रिश्ता है। देश केवल पहाड़ या उसकी सीमाओं से नहीं बनता, देश इन पहाड़ों और सीमाओं के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनसे बनता है और उनके रिश्ते कैसे हैं, यह भी देश की एकता के लिए बहुत आवश्यक तत्व या सूत्र है। तो हमें पहले यह रिश्ते जोड़ने की बात करनी होगी और फिर, दूसरे, हमें देखना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसा मैंने कहा कि वे अनट्रेंड सिपाही हैं, वे भी चाहते हैं कि भारत की सीमाओं की रक्षा हो। वे डरते भी हैं,

क्योंकि अगर चीनी आक्रमण हुआ तो तो सबसे पहले नाथुला की चौकी पर चीनी सैना पहुंचेगी और सबसे बड़ा तथा पहला मुकाबला तो सिक्किम के लोग ही करेंगे। अगर सिक्किम के लोगों के मन में यह भाव नहीं होगा कि यह देश हमारा है, देश की रक्षा करनी है, उसके लिए जान भी न्योछावर करनी पड़े तो हम करेंगे, तो फिर देश की रक्षा नहीं हो पाएगी और यह भाव हम तभी पैदा कर पाएंगे जब उनसे हमारा तादाम्य होगा, हमारा उनसे लगाव होगा और उनको यह लगेगा कि जो संसाधन हैं, उनका बंटवारा ठीक हो रहा है। अब एक तरफ दिल्ली में बारह मास सड़कें बनती रहती हैं। यहां पर जो संसाधन हैं, जनता का पैसा है, उस पैसे का कितना हिस्सा कहां पर खर्च होगा, इसका बंटवारा ठीक तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को यह लगेगा कि हमारे लिए वह सही तरह से नहीं खर्च हुआ, तो विषमताएं बढ़ेंगी। प्रस्तावक महोदय ने ठीक ही कहा है कि अगर हम योजना आयोग के उस पुराने फार्मूले को मानें कि आबादी के हिसाब से संसाधनों का बंटवारा होगा तो उसके अनुसार तो सिक्किम का कभी नम्बर ही नहीं आएगा, छोटे-छोटे प्रदेशों का कभी नम्बर ही नहीं आएगा। इसलिए आबादी और आबादी के साथ विकास की गति कैसी रही और उसके साथ ही साथ उनका भारत के विकास में, भारत की सुरक्षा में महत्व क्या है, इन तीनों का आधार होना चाहिए, तभी आप संसाधनों का ठीक तरीके से बंटवारा कर पाएंगे, वरना जो पहले से विकसित हैं या जिन्होंने अब तक संसाधनों का सर्वाधिक फायदा उठाया है, वे और आगे बढ़ जाएंगे और जिनको संसाधन कम मिले हैं, वे लगातार पिछड़ते जाएंगे। तो देश में जो सम्यक विकास है, जिसको आप balanced development कहते हैं, वह सम्यक विकास नहीं हो रहा है। अगर सम्यक विकास नहीं होगा तो उससे हमारी क्षेत्रीयता विषमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय विषमता विद्रोह का या विघटन का बहुत बड़ा कारण बनती है। इसलिए क्षेत्रीय विषमता को खत्म करने के लिए सिक्किम को बहुत ही सं ुदर और खूबसूरत बनाने के लिए और उसकी प्राकृतिक सुंदरता या सौंदर्य का सर्वाधिक फायदा उठाने के लिए, देसी तथा परदेसी, दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि सिक्किम का चतुर्मखी विकास किया जाए.....।

इसके लिए अगर संसाधनों की आवश्यकता हो, तो विशेष उपाय करके संसाधन जुटाए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लेपचा जी ने जो संकल्प आज यहां सिक्किम राज्य के विकास के बारे में प्रस्तुत किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने अपनी बातें यहां कहीं और उन्होंने बड़े सटीक तरीके से बताया, मैं उनसे सहमत हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 1975 में भारत में सिक्किम का विलय हुआ था, आज उसे बने हुए 35 साल हो गए हैं, लेकिन इन 35 सालों में सिक्किम का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, वह आज तक नहीं हो पाया है, यह बड़े दु:ख की बात है, यह बड़ी विडंबना है। प्रस्तावक महोदय ने अपना प्रस्ताव रखते हुए बताया कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सिक्किम के पास जो अपनी प्राकृतिक संपदा है, यदि थोड़ा भी प्रयास किया जाता, तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन इन 35 सालों में कुछ नहीं हो पाया। उसका infrastructure development, economic development नहीं हो पाया है और इस नाते यह पिछड़ा हुआ है। इसलिए प्रस्तावक महोदय ने जो संकल्प यहां पर रखा है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। सिक्किम में चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और यह अंतराष्ट्रीय सीमा में है तथा यह चीन, भूटान और नेपाल से जुड़ा हुआ है। सिक्किम का दुर्भाग्य यह है कि इस राज्य को देश के दूसरे राज्यों से सीधे जोड़ने के लिए कोई रेलवे लाइन या हवाई सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहां की lifeline केवल एक हाइवे है – 31A, यह नेशनल हाइवे है और सिक्किम की lifeline है, लेकिन विभिन्न कारणों से ज्यादातर यह बाधित रहता है – कभी बंद के कारण, कभी landslide के कारण, कभी किसी और कारण से यह बंद हो जाता है। इसलिए यह जो lifeline है – 31A, इसकी जो दुर्दशा है, अभी हमारे माननीय साथी ने बताया कि जब वे सिक्किम गए, तो उनका किस तरह का अनुभव रहा। कम से कम

जो नेशनल हाइवे है, उसको सही तरीके से रखना, उसको मैंटेन करना, इसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो, तो केन्द्र सरकार की ओर से बजट देना, यह मदद कभी सिक्किम को नहीं मिली है। वहां के लोग जितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, उस हिसाब से केन्द्र सरकार को सिक्किम की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं सिक्किम के पड़ोसी राज्य से आता हूं, मेरा क्षेत्र दार्जिलिंग, उससे बिल्कुल लगा हुआ है। मैंने सिक्किम की जनता को बहुत करीब से देखा है। वहां की जनता बहुत शांतिप्रिय है, वहां पर बहुत कठिनाइयां हैं, उनकी जीवन शैली बहुत कठिन है। वहां की आम जनता कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि भी उतनी लाभदायक नहीं है, क्योंकि उसका उत्पादन इतना संतोषजनक नहीं है। दो-तीन छोटे-मोटे उद्योगों को छोड़कर, वहां पर रोज़गार का दूसरा कोई साधन नहीं है। वहां के लोग आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं, फिर भी वहां की जनता कभी भी कोई शिकायत, कोई agitation, कोई दंगा-फसाद या इस तरह की गतिविधि नहीं करती है और वे लोग शांतिप्रिय हैं। इतनी समस्या होने के बावजूद, विकास में इतनी कमी के बावजूद, वहां के लोग इस देश के गणतांत्रिक परिवेश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता और एकता की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से सिक्किम को सबल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटा राज्य होने के कारण यहां आर्थिक विकास और संसाधनों की कमी रही है।

यहां के चौतरफा विकास हेतु केन्द्र सरकार गंभीरता से सोचे। शिक्षा, रोजगार और कृषि जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सटीक योजना बनाए। महोदय, सिक्किम में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग और हर भाषा के लोग आपस में प्रेम और सद्भावना से रहते हैं और देश की अखण्डता की रक्षा के लिए उन लोगों की जो भावना है, उसकी सरकार कम से कम कद्र करे और ज्यादा से ज्यादा सिक्किम के विकास पर ध्यान दे। माननीय सदस्य यह जो संकल्प लाए हैं, मैं इनसे सहमत हूँ। सिक्किम के विकास के साथ-साथ यथाशीघ्र इसे रेल लाइन और हवाई सेवा द्वारा देश के अन्य क्षेत्रों के साथ भी जोड़ा जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 का बयान माननीय प्रस्तावक ने भी किया है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया है कि इसकी जो स्थिति है, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई वैकल्पिक रास्ते के लिए केन्द्र सरकार विचार करे।

महोदय, सिक्किम एक हिमालयन क्षेत्र है और यह हिमालयन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न जाति का जो अपना हेरिटेज और कल्चर है, यह प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। सिक्किम से जुड़ा हुआ जो दार्जीलिंग का क्षेत्र है, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल बनने की संभावना है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार कम से कम सिक्किम को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र घोषित करे और ऐसा होने से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। इसके साथ ही साथ, यहां के जनजाति लोगों की जो भाषा और संस्कृति है, इसका भरपूर खजाना है, इसके संरक्षण और अध्ययन हेतु केन्द्र सरकार को भरपूर सहायता देनी होगी। साथ ही साथ, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार होगी, इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना होगा। अभी हाल में जो सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उसको भी अधिक राशि प्रदान करें, ताकि शैक्षिक रूप से सिक्किम और मजबूत हो। इसके अलावा और जो दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे तकनीकी क्षेत्र, उच्च शिक्षा का क्षेत्र, आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के लिए सिक्किम की जनता को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए भी कम से कम सिक्किम यूनिवर्सिटी के विभिन्न faculties, जैसे विभिन्न engineering faculties और अन्य तकनीकी faculties को और मजबूत करें तथा तकनीकी शिक्षा को और मजबूत करे। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा के लिए Engineering Centre for Excellence बनाया जाए और मेडिकल कॉलेज का भी विस्तार किया जाए। सिक्किम में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन है। वहां पर अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी होती है, तो उसे इलाज के लिए दिल्ली या भेल्लोर जाना पड़ता है या कहीं बाहर जाकर

इलाज कराना पड़ता है। इसलिए सिक्किम में भी "एम्स" टाइप के हॉस्पिटल का विस्तार किया जाए। माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके साथ मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ।

महोदय, श्री ओ.टी. लेपचा जी द्वारा जो संकल्प लाया गया है, मैं उसका एक बार फिर से भरपूर समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार इस पर response करेगी और सिक्किम की जनता की जो integrity है, जो भावना है, उसकी कद्र करेगी। जिस प्रकार से वहां के लोगों ने देश की अखण्डता की रक्षा के लिए शांतिप्रिय ढंग से प्रयासरत है, जिस प्रकार से वे लोग एक भारतीय होने का गर्व करते हैं, उसी हिसाब से उन पर भी सरकार का ज्यादा ध्यान होना चाहिए, मैं ऐसा आशा करुंगा। कभी-कभी प्रेस मीडिया में आता है कि कभी अरुणाचल प्रदेश और कभी सिक्किम में सब चीन ने ले लिया, सब चीन के साथ जा रहा है। दो महीने पहले शायद किसी अखबार में ऐसा आया था, जिसके कारण पर्यटन क्षेत्र पर इतना असर हुआ कि वहां जो पर्यटक जाना चाहते थे, वे नहीं गए और जो लोग वहां गए थे, वे लोग भी डर कर वापस आने लगे। वहां इस तरह की भयावह स्थिति पैदा की जाती है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि इस तरह की कोई भी अफवाह हो तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि इसके कारण सिक्किम की जो आर्थिक समृद्धि है, वहां की जो शांति है, वह भंग न हो। इसी के साथ मैं इनके संकल्प का समर्थन करता हूं।

SHRI R.P.N. SINGH: Sir, if your permit, I would like to intervene here.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, you can intervene.

SHRI R.P.N. SINGH: I would just like to bring to the notice of the House that there has been a lot of discussion on the National Highway 31-A which links Sikkim to the rest of the country. I would just like to bring to the notice of the House that we have taken a lot of measures to improve that road. Mr. Vice-Chairman, Sir, if you give me some time, I would just reply to that.

The total length of the road from Sevoke to Gangtok is about 80 kilometres. There are 77 identified critical locations on this road. The Ministry has approved estimates for improvement of 69 locations at an estimated cost of Rs. 46 crore. BRO has started the work. The estimates for the remaining 8 locations will also be approved by the Ministry as and when they are finalised by the BRO. For the 2-laning of the entire NH-31A, including the improvement of critical locations, the Cabinet has approved investment of Rs. 700 crore on 30.07.2009. The estimates are under preparation by BRO. These will be sanctioned as soon as they are finalized. There are difficulties in forest clearance and land acquisition in West Bengal portion which are being sorted out by the State Government.

Another road which my Ministry has taken up is the Gangtok-Nathula Road. This is about 90 km long State road connecting Ranipul to Nathula, the Chinese Border, the issue which the hon. Member had raised. The Ministry has approved estimates for improvement of entire road to 2-lane standards at an estimated cost of about Rs. 600 crore. In 67 km length, the BRO is executing the work and in about 23 km length, Sikkim PWD has invited tenders for Gangtok Bypass.

I would also like to bring to the notice of the House the Special Accelerated Road Development Programme of the North-East. Sikkim after Assam, is the State which has got the highest grant of Rs. 650 crore. We have taken in principle decision about another alternate high

way to provide connections to Gangtok being landlocked and because there being always demonstrations on NH 31-A. The road getting closed down frequently, a high level team, headed by the Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, visited National Highway 31-A on 19.11.2009. The team has recommended a number of engineering measures to be adopted to ensure efficient traffic movement on NH-31A. In fact, the Prime Minister himself has taken interest in this matter. The Government of West Bengal has been requested to take all the necessary actions to see that this road is never blocked and for all improvement work, forest clearances and land acquisition, etc, which are required, should be taken up immediately.

Another proposal which we have moved regarding Sikkim is this. There are 4 district headquarters in the whole of Sikkim. Gangtok would be connected by a 2-lane highway through NH-31A. The proposal for 2-lane connectivity of remaining three district headquarters (Namchi, Gayzing and Mangam) has been included under Phase B of SARDP-NE. The Ministry is now approaching the Cabinet for advancing the connectivity to Namchi and Gayzing from Phase B to Phase A. This would pave the way for construction and improvement of 112 km State roads. 2-lane connectivity of Mangam is proposed to be taken up during the 12th Plan.

I can assure you, Sir, that the Government of India is extremely keen and is taking all important measures to improve roads of Sikkim. In fact, there is another proposal to construct an alternate highway of about 242 km length form Chalsa on NH 31 to Ranipul which has been approved by the Government in-principle and the BRO is engaged in preparation of DPR and feasibility reports for this Highway is on.

So, I would like to tell the Members and assure them that my Ministry, as far as the roads are concerned, is trying to connect Sikkim. We are really taking all the necessary steps and we can assure them, as lot of Members have raised the issue of NH-31A, that they can be rest assured that the work is being carried out and Government has released money for that Highway.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Minister. Thank you very much. Now, Mr. Biswajit Daimary.

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम) : महोदय, मेरे मित्र श्री ओ.टी. लेपचा जी ने जो सिक्किम राज्य के लिए यहां पर resolution रेज़ किया है, उस पर बहस करने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं, लेपचा जी का जो संकल्प है, जो resolution है, उसका समर्थन करता हूं। यह बहुत ही genuine और महत्वपूर्ण संकल्प है। इस विषय पर हमारे कुछ मित्र उनके सपोर्ट में बोल चुके हैं। इसी तरह से मैं भी कुछ प्वाइंट्स इसी में जोड़ना चाहता हूं। जो भी हो, यह एक sentiments की बात है। हमारे मिनिस्टर साहब ने सुनने के लिए इतना धीरज नहीं रहा इसीलिए in advance रिप्लाई में, उनके मंत्रालय की तरफ से वे क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। यही नहीं, अभी रास्ते का प्रस्ताव तो सुना है लेकिन ऐसा भी ऐवीडेंस है – सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है – वहां तक 15 साल बीत गए हैं, भारत सरकार की ओर से जितनी भी परियोजनाएं वहां के लिए सिद्धांततः ली गयी थीं, जो भी प्रोजेक्ट्स लिए गए थे, वे आज तक नहीं हुए। ऐसा न हो कि आज जो हमारे मंत्री जी ने यहां पर बताया है और सिक्किम के नैश्नल हाईवे – ए के लिए जो परियोजना की बात उन्होंने कही है, वह भी टाइमली न हो पाए। महोदय, इस प्रस्ताव को लेने में कोई

मुश्किल नहीं है क्योंकि यह देश की भलाई के लिए है। मंत्री महोदय स्वयं यहां हैं, जो रास्ते के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय खुद वहां एक बार जाएं और थोड़ा सा वहां पर देखें। जितने भी वहां पर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स लोग गए हुए हैं, आप देखें कि प्रेक्टीकली फील्ड में क्या हो रहा है क्योंकि नैश्नल हाईवे-31, जो डबल लेन बनने की बात थी, बंगाल को पार करने के बाद, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। वह गुवाहाटी तक जाता है और उसका असर नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स पर पड़ता है। इस तरह की हालत है। कृपया इस पर ध्यान दें। इसी तरह से टूरिज्म के डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि इसको इंटरनैशनल लैवल के टूरिज्म में लाया जा सकता है मैं चाहता हूं कि टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से इस पर कुछ ध्यान दिया जाए। वहां खुद मंत्री जी जाएं ताकि उसको देखने के बाद वह स्वयं कुछ व्यवस्था ले सकें। इसी तरह से एयर कनेक्टिविटी की बात है। यह कोई समस्या की बात नहीं है। सिविल एविएशन की तरफ से वहां – बड़ी फ्लाइट नहीं होने से, बोइंग फ्लाइट नहीं होने से भी – कम से कम हेलीकॉप्टर की सर्विस तो कुछ साल के लिए की जा सकती है। इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। रेलवे को भी दुरुस्त किया जा सकता है। रेलवे के रास्ते के लिए काम करने के लिए टेक्नीकली कोई प्रॉब्लम नहीं है – भूटान में हमारा इंडिया ही सड़क का काम कर रहा है। भूटान और सिक्किम लगे हुए हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूं कि भूटान हमारे बोडोलैंड के साथ लगा हुआ है। वहां पर more than 3000 km सड़क पर हमारा बीआरओ काम कर रहा है और मैंटेनेंस का काम भी देख रहा है। अगर इस हिली एरिया में यह सारा काम कर सकता है तो सिक्किम में क्यों नहीं हो सकता? इंडिया का जो यह सेक्टर है, वह बहुत ही बैकवर्ड है, उसमें क्यों नहीं कर सकता है – जरूर कर सकता है। आज भारत के साथ मर्ज हुए 35 साल बीत गए है। आज धीरे-धीरे सिक्किम के लोग थोड़ा दुखी और चिंतित होने लगे हैं कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होने के बाद क्या मिला, क्या नहीं मिला, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। यह अच्छी बात नहीं है। आज लेपचा जी ने जो बात यहां पर बताई है, उसका इंगित अच्छा नहीं है क्योंकि हमारा एक्सपीरिएंस है कि नॉर्थ ईस्ट में आज बहुत सारे लोग, बहुत सी ऑरग्नाइज़ेशंस भारत से अलग होने के लिए संग्राम कर रही हैं। आज हम एनएससीएन की बात डिनाई नहीं कर सकते हैं। सब जानते हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, आज हम उल्फा की बात डिनाई नहीं कर सकते हैं, एनडीएफबी की बात डिनाई नहीं कर सकते हैं जो सिक्किम तक पहुंचने वाले हैं। एनडीएफवी और नेपाल के साथ माओवादियों के आज आपस में अच्छे रिलेशंस हैं, उल्फा के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और वे लोग सिक्किम होकर ही नेपाल तक जाते हैं। आज तक सिर्फ वे लोग सिक्किम में एक्टिविटीज इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को शेल्टर चाहिए नेपाल तक जाने के लिए, उस रास्ते को चाहिए। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सिक्किम के लोग ऐसा फील नहीं करें कि हम गलती से इंडिया के साथ मर्ज हो गए हैं। क्योंकि बराबर में चायना है, वह भी हमारे लिए भयानक स्थिति है। आज अरुणाचल के लिए भी कितना चिंताजनक विषय है। आज यहां पर एक्सटर्नल एफ्फेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया कि 27 अक्तूबर को बंगलौर में ट्रिपार्टाइट मीटिंग हुई थी। वहां पर जितनी भी बात की गई, उसमें अरुणाचल के मुद्दे को नहीं उठाया गया। वहां पर हालत इतनी खराब हो गई, इससे चायना को लेकर सारे देश के लोग चिंतित हैं। तो इसी तरह का हाल है। हमारे जो मिनिस्टर लोग होते हैं, अगर वे इस चीज को फील नहीं करते हैं, इसके ऊपर कोई चिंता नहीं करते हैं तो देश की सुरक्षा कैसे होगी तथा वहां का आदमी खुद को कैसे सिक्योर्ड फील कर सकता है? अभी अरुणाचल की हालत बहुत खराब है। अरुणाचल के साथ असम है, बाकी अन्य स्टेट्स हैं, जो बहुत चिंतित हैं। तो इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और शायद ऐसी ही समस्या आज सिक्किम में भी हो जाएगी। हमारे जो विषमतावादी लोग हैं, जो संग्रामी विषमतावादी लोग हैं, वे ही लोग धीरे-धीरे इस मौके का फायदा उठाएंगे तथा लोगों के सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। इसके साथ ही वे ही लोग चायना के साथ लिंक करेंगे तथा चायना उनको थोड़ा सा उठाएगा, उनको आर्म्स देगा, पैसा देगा तथा काम करने के लिए व्यवहार करेगा। इसी तरह अरुणाचल में भी होने जा रहा है। वहां के अखबारों में भी आया है कि अरुणाचल

का जो एरिया है, उसको बहुत इंफ्लुएंस किया है और वे ही लोग चायना के साथ लिंक करेंगे, जिस तरह अल्फा, एन0डी0एफ0बी0 ने बंगला देश के साथ कर रहे हैं और सीमाओं पर समस्या हो रही है। तो अगर दिल्ली से कोई इसको इंपोर्टेंस नहीं मिलेगा, केन्द्रीय सरकार की तरफ से इसको कोई इंपोर्टेंस नहीं दिया जाएगा तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सकेगा। तो इसको सही ढंग से देखना चाहिए। आज हमारा जो संविधान है वह इसको कम्पलीटली कवर नहीं कर सका, इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसमें इतना जल्दी-जल्दी अमेंडमेंट करके काम करना भी मुश्किल है। इसलिए आज लेपचा जी जो प्रस्ताव लाए हैं, इसी तरह के प्रस्ताव को जोड़िए, भारतवर्ष के सारे स्टेट्स को, सारे कोने को, सारे सैक्टर्स को डेवलप करने के लिए इस पार्लियामेंट में कुछ व्यवस्था लेनी पड़ेगी। सिर्फ मंत्रालयों की जो पॉलिसी है, सरकार की जो पॉलिसी है, भारत के विकास करने की जो नीति है, इसके ऊपर निर्भर करने से हमारा देश कभी उन्नत नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि पं0 जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधान मंत्री के कार्यकाल आए हैं सारे भारत को डवलप करने के लिए, वे कामयाब नहीं हो पाए, सब नाकाम रहा, जिसके कारण आज तक अनपढ़ आदमी भारतवर्ष में हैं, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उनको खाने के लिए खाना भी नहीं है, ऐसे लोग आज भारतवर्ष में हैं। यह इसलिए है, क्योंकि हम यहां पर अच्छी पॉलिसी इस देश के लिए नहीं ला सके हैं। आज हम दिल्ली में शिक्षा के लिए जितना ऊपर लेविल में चिंता करते हैं, उसको ही हम सारे देश में लागू करते हैं, ऐसा हमको लगता है। हम जो यहां देख रहे हैं, वही इंडिया में हो रहा है। लेकिन दिल्ली तो अलग है, असम अलग है, बंगलौर अलग है, मुम्बई अलग है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे दुखदायी बात यह है कि अगर इंडिया में हर मंत्रालय की तरफ से देश को उन्नत करने के लिए कुछ पौलिसी लेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा सा खोटा में रख लेता है, अगर उसमें हो गया तो हो गया। आज शिलांग में आई0आई0एम0 – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट दिया है। सारे नॉर्थ ईस्ट को बताते हैं कि आप लोगों को यह-यह दिया है। गोहाटी में आई0आई0टी0 बनाया है। नॉर्थ ईस्ट के सारे लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को तो आई0आई0टी0 दिया है। लेकिन क्या वह सम्भव है और यह सिक्किम के लिए कोई फायदाजनक होगा? क्या मिजोरम के लोगों के लिए कोई फायदाजनक होगा? बात की तो चिंता करनी चाहिए। इसलिए इंडिया के सब स्टेट्स में ऐसा Institute होना चाहिए। आज इतना प्रॉब्लम हो गया है, मैं मेडिकल के बारे में बात कर रहा हूं, आज गांवों में डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर कैसे होगा, सारे स्टेट्स के लोग दो-तीन मेडिकल कॉलेज में जितनी सीटें हैं उनमें पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर धनी लोगों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर वे बाद में दिल्ली आ जाते हैं तथा फिर फॉरेन में जाकर नौकरी करने लगते हैं। धनी लोगों के बच्चे वहां वापिस नहीं जाते हैं, क्योंकि धनी लोगों ने उनको वहां पैसा देकर पढ़ाया है, ट्यूशन दे देकर मेरिटोरियस बनाया है, इन्ही लोगों का नम्बर आता है तथा एंट्रेंस में यही लोग पास होते हैं। क्योंकि इन लोगों ने खर्चा किया है, पास होने के बाद इनको पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं, तथा वे लोग वापिस नहीं आते हैं।

आज गांव में सेवा करने के लिए हमारे पास कोई एमबीबीएस डाक्टर नहीं है। हम लोग इतने डाक्टर प्रड्यूस कर रहे हैं, लेकिन देश की सेवा में हम उनको लगा नहीं सके, हम सब कुछ बाहर के लिए कर रहे हैं। गुवाहटी में जो आईआईटी पास करता है, वह गुवाहटी में नहीं होता है, उसे इधर आना पड़ता है। कभी-कभी तो उनके लिए इंडिया में नौकरी नहीं होती है, वे फॉरेन चले जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है ? अगर छोटा-मोटी इंजीनियर की पढ़ाई करने का मौका होता, तो उसमें गांव के गरीब लोग पढ़कर कम से कम गांव में किसी न किसी प्रोजेक्ट में, किसी फैक्ट्री को चलाने में उनकी मदद करते। लेकिन सब बड़े आदमी के बड़े लड़के, बड़े इंस्टीट्युशन्स में पढ़ गए, सब विदेश चले गए और आज देश में काम करने वाले आदमी नहीं हैं। हम ह्यूमैन रिसोर्स की बात करते हैं, ये कहां से आएंगे। हमारी इसी तरह की समस्या है और उस तरफ देखना जरूरी है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं इसलिए आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सिक्किम के लिए स्पेशली एक Action Plan बनाकर, उसको दिल्ली जैसा डेवलेप करने के लिए, मुम्बई

जैसा डेवलेप करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। वहां की इकोनोमी को डेवलेप करने के लिए सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों ने असम में आंदोलन किया है, आज 42 साल हो गए हैं, 1967 से हमनें आंदोलन किये हैं। सिक्किम 1975 से इंडिया के साथ जुड़ गया है। आज तक वहां की अवस्था 42 साल पहली जैसे ही है। कोई अच्छा आदमी, जानने वाला आदमी, यहां प्रस्ताव लाता है, तो यह easily pass हो जाता है। बुंदेलखंड बनाने की बात है। बुंदेलखंड बनाने का प्रस्ताव आ गया, वह तो पास नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए हजारों करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज के नाम पर दे दिया गया हैं। हम लोगों को बोडोलैंड मिला, Bodoland Territorial Council इसके लिए 500 करोड़ रुपये, पांच साल के लिए हमको दे दिए और इसके लिए सरकार की तरफ से आफिसियली यूज करने में कोई हैल्प नहीं की क्योंकि हमारे पास न मैन पावर है, न इंजीनियर्स हैं, तो भी हम लोगों को पैसा मिला था, तो हमने जबरदस्त काम करा दिया। इसके बाद UCs चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए और आफिसियल प्रॉसिजर लेट हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक में बोल दिया कि Bodoland Territorial Council को जो 500 करोड़ रुपया दिया था, उसके यूटिलाइजेशन से सेटिसफाईड नहीं हैं। हम को दोष दे दिया। इसमें दोष किसका था ? जिस तरह से बुंदेलखंड के लिए sympathy दिखाई, नार्थ-ईस्ट में N.C. Hills में जो घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। वहां पर सिक्स शैड्यूल में ऑटोनामस काउन्सिल दे दी है, लेकिन उसको डेवलेप करने के लिए कभी चिंता नहीं की। वहां पर रास्ता नहीं है, वहां पर कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, वे लोग इंडिया के सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं, वे लोग संविधान के बारे में क्या जानते हैं ? वे लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हमारे भारतवर्ष के एक्सपर्ट्स, जो कांस्टीट्युशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग सिस्टम के एक्सपर्ट्स हैं, वे लोग बैठकर वहां के लोगों के लिए, जो जॉब ढूंढ़ रहे हैं, उनके लिए कौन-सी व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए क्यों कदम नहीं उठाते हैं ? सिर्फ उन लोगों को ही बोलते रहते हैं कि आप लोग बोलिए कि आपके लिए क्या करना है ? हमको क्या पता है कि हमको क्या करना है। हमको सिखाया ही नहीं गया कि क्या करना है ? हमारे यहां पर एजुकेशन की व्यवस्था ही नहीं की गई है। आज तक असम में हजारों स्कूल पब्लिक चला रही है, फ्री में चला रही है, बिना पैसे में टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें से बहुत से रिटायर्ड भी हो गए हैं और धीरे-धीरे ये स्कूल-कॉलेज बंद होने वाले हैं, लेकिन इस विषय पर हमारा देश गंभीर नहीं है। अगर कोई उनसे यह नहीं पूछेगा कि भाई आप लोग ऐसे क्यों हो, थोड़ा शांति से रहना सीखो, थोड़ा मिल-जुलकर रहना सीखो, इसको कोई कैसे सुनेगा जिसका कोई भविष्य नहीं है, वह कैसे शांति से रहेगा। अगर मुझे शांति पीस नहीं है, आपको पार्टी करते देखता हूं, नाच-गाना करते हुए देखता रहता हूं, तो मेरा पत्थर मारने का दिल जरूर होगा, आपका भी जरूर होगा..।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, conclude your speech.

श्री बिश्वजीत दैमारी: इसी तरह की हालत है, इसलिए मैं आपके जरिए से अनुरोध करता हूं कि जितने भी हमारे देश को नेतृत्व देने वाले मंत्री हैं, जो यहां पर मौजूद हैं, वे इसको देखें। वे अरूणाचल प्रदेश में भी जाएं, मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारे प्रदेश में भी आइए। जरूरत पड़ी तो आने जाने का पैसा हम लोग देंगे और आप वहां पर क्या मदद कर सकते हैं, इसको आकर आप देखिए। धन्यवाद।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान सांसद साथी श्री ओ.टी. लेपचा जी ने सिक्किम के विकास के लिए सदन में एक resolution पेश किया है।

THE VICE-CHAIRMAN: Hon. Members, the time is over. It is 5.00 p.m. This discussion will continue on the next day of the Private Members' Resolution. The House is adjourned to meet at 11.00 a.m. on Monday, the 30th November, 2009.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 30th November, 2009.